राष्ट्रीय संस्करण

दैनिक जागरण

वर्ष 3 अंक 163

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, गुरुवार, 21 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

सत्य नडेला बने फार्च्यून बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर

>> 12

सरोकार

'बेटी पढ़ाओ' ही नहीं, अब 'बेटी को और पढ़ाओ'

नई दिल्ली : ग्रामीण भारत में बेटियों को 'और पढ़ाने' की आवश्यकता है। सुशिक्षित

समाज के निर्माण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए यह अनिवार्य है। दैनिक जागरण ने समाचारीय अभियान छेड़ा है- बेटी को और पढ़ाओ...। शुरुआत हरियाणा से हुई है। (पेज-10)

जागरण विशेष

कठिन रेगिस्तान में जीवन को आसान बना रहा 'उरमूल'

जयपुर : राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में लोगों को पानी ही नहीं जीवन से

जुड़ी हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसी संघर्ष को आसान बना रहा है उरमूल यानी उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड। (पेज-10)

न्यूज गैलरी

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

नए साल में देश को मिलेगा पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

नई दिल्ली : अगले साल यानी जनवरी तक देश को पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सीडीएस की नियुक्ति के तौर-तरीकों को तय करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट सौंप देगी।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 12

इंट्रा-डे में सेंसेक्स का रिकॉर्ड 12 हजारी बनते रह गया निफ्टी

मुंबई : भारतीय शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी का रुख रहा। इंट्रा-डे में सेंसेक्स ने नया रिकॉर्ड दर्ज किया। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 181.94 अंक की बढ़त के साथ 40,816.38 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं एनएसई के 50 शेयरों वाला निफ्टी 59 अंक की उछाल के साथ 11,999.10 पर बंद हुआ।

अंतरराष्ट्रीय ▶ पृष्ठ 13

हांगकांग मानवाधिकार बिल अमेरिकी सीनेट से पारित

वाशिंगटन : हांगकांग के लोकतंत्र समर्थकों के प्रति एकजुटता दिखाते हुए अमेरिका की संसद ने हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र अधिनियम, 2019 को सर्वसम्मति से पास कर दिया। यह बिल ट्रंप प्रशासन को इसका आकलन करने की शक्ति देगा कि अशांति के कारण हांगकांग को मिले विशेष दर्जे में बदलाव लाना उचित है।

आजकल ▶ पृष्ठ 16

उल्कापिंडों में है पृथ्वी पर जीवन लाने वाला शुगर मॉलीक्यूल

वाशिंगटन : वैज्ञानिकों को पहली बार उल्कापिंडों में 'शुगर मॉलीक्यूल' की उपस्थिति का प्रमाण मिला है। धरती पर जीवन की शुरुआत होने में 'शुगर मॉलीक्यूल' की अहम भूमिका मानी जाती है। इस खोज से पृथ्वी पर जीवन पनपने में उल्कापिंडों की भूमिका को मजबूती मिली है। पीएनएएस जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि जैविक प्रक्रिया के लिए शर्करा महत्वपूर्ण है।

पांच कंपनियों के साथ विनिवेश का सबसे बड़ा अभियान शुरू

कैबिनेट के फैसले ▶ भारत पेट्रोलियम, एससीआइ, कॉनकोर की रणनीतिक बिक्री के फैसले पर मोदी सरकार की मुहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भारत पेट्रोलियम पर नियंत्रण भी खरीदार को सौंप दिया जाएगा
- बिजली क्षेत्र के दो सरकारी उपक्रम एनटीपीसी को सौंपे जाएंगे
- कुछ उपक्रमों में सरकारी नियंत्रण रखते हुए हिस्सेदारी 51 फीसद से नीचे लाई जाएगी

नई दिल्ली में बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देतीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। प्रेट्र

अन्य प्रमुख फैसले

- सवा लाख टन प्याज को आयात करने को भी सरकार की हरी झंडी
- टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम शुल्क भुगतान में दो वर्षों की राहत
- आइएफएससी में सारे वित्तीय नियामक एक ही नियंत्रण में काम करेंगे

केंद्र सरकार ने वादे के मुताबिक सरकारी कंपनियों के रणनीतिक विनिवेश शुरू करने का फैसला किया है। पहले चरण में पांच कंपनियों भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (बीपीसीएल), शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआइ), कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (कॉनकॉर्प), टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (टीएचडीसीआइ) और नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (नीपको) की बिक्री की जाएगी। विनिवेश प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा निवेशकों के हिस्सा लेने के लिए सरकार ने अपनी हिस्सेदारी के साथ ही प्रबंधन नियंत्रण भी खरीदार कों सौंपने का फैसला किया है। टीएचडीसीआइ और नीपको की हिस्सेदारी व प्रबंध नियंत्रण सरकारी क्षेत्र की एक अन्य कंपनी एनटीपीसी को सौंपी जाएगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने बैठक में बुधवार को यह फैसला लिया। इस फैसले के क्रियान्वयन से सरकार के खजाने में बड़ी वृद्धि होगी। सिर्फ बीपीसीएल से ही 56 हजार करोड़ की राशि हासिल हो सकती है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीसीईए के फैसलों के बारे में बताया, 'सरकार का फैसला है कि कई उपक्रमों में वह अपनी हिस्सेदारी 51 फीसद से कम करेगी, लेकिन कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण बना रहेगा। ये किस तरह के उपक्रम या कंपनी होंगे, इसके बारे में बाद में फैसला किया जाएगा।' माना जा रहा है कि सरकार का यह फैसला मुख्य तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों व अन्य वित्तीय संस्थानों पर लागू होगा, क्योंकि वहां सरकार अपनी हिस्सेदारी 51 फीसद करके ज्यादा फंड जुटा सकेगी, लेकिन बैंकों या वित्तीय संस्थानों पर सरकार का नियंत्रण ही बना रहेगा। इस तरह के प्रस्ताव पर वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार और बाद में यूपीए-2 में भी विचार किया गया था। माना जा रहा है कि सीसीईए का यह फैसला दुनिया के निवेशक समुदाय को भारत में आर्थिक सुधारों के प्रति एक नये भरोसे का संचार करेगा।

सीतारमण ने बताया कि बीपीसीएल में केंद्र की 53.29 फीसद हिस्सेदारी है, जिसे नए रणनीतिक साझेदार को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हालांकि असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी (एनआरएल) में बीपीसीएल की 61 फीसद हिस्सेदारी को नहीं बेचा जाएगा। एनआरएल को किसी दूसरी सरकारी तेल कंपनी को सौंपने की संभावना है। हालांकि जहाजरानी क्षेत्र की एससीआइ में केंद्र अपनी पूरी 63.75 फीसद हिस्सेदारी बेच देगी। कॉनकोर में भी 54.8 फीसद में से 30.8 फीसद की रणनीतिक बिक्री की जाएगी। तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने कुछ सार्वजनिक उपक्रमों की रणनीतिक बिक्री की थी, लेकिन उसके बाद यूपीए के 10 वर्षों तक इसे अमल में नहीं लाया गया। मोदी सरकार पहले कार्यकाल के दौरान भी इसे नहीं आजमा सकी, लेकिन अब अर्थव्यवस्था के समक्ष कई तरह की चुनौतियों को देखते हुए इस तरीके को फिर से आजमाया जा रहा है। ज्यादातर कंपनियों की रणनीतिक बिक्री का काम इसी वित्त वर्ष में पूरा किया जाएगा। उन्होंने संकेत दिए कि कुछ बड़े फैसलों की घोषणा इसी माह हो सकती है। बीपीसीएल में सउदी अरैमको और शेल जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां रुचि रखती हैं।

देशभर में लागू होगा एनआरसी : शाह

संसद में दो टूक ▶ इसका धर्म से कोई लेना-देना नहीं, सब होंगे शामिल

पूरे देश के साथ असम में फिर से तैयार होगा नागरिकता रजिस्टर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

संसद सत्र के दौरान बुधवार को राज्यसभा में एनआरसी पर बोलते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। प्रेट्र

अमित शाह ने राज्यसभा को बताया कि सरकार पूरे देश में एनआरसी लागू करेगी। साथ ही उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) का किसी भी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। किसी को इससे डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तावित नागरिकता संशोधन कानून से एनआरसी का कोई लेना-देना नहीं है। दोनों अलग-अलग चीजें हैं।

अमित शाह ने राज्यसभा को बताया कि एनआरसी में देश के सभी संप्रदाय के लोगों को शामिल किया जाएगा। किसी खास संप्रदाय को इससे बाहर रखने का कोई प्रावधान नहीं है। फिलहाल असम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से एनआरसी को लागू किया गया, लेकिन जब पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा, तो उसमें असम भी शामिल होगा। यानी असम में दोबारा एनआरसी लागू किया जाएगा। मौजूदा एनआरसी के ड्राफ्ट से बाहर रह गए लोग ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास ट्रिब्यूनल में अपील करने के लिए पैसे नहीं हैं, तो असम सरकार उन्हें मुफ्त वकील मुहैया कराएगी।

अमित शाह ने साफ किया कि एनआरसी और नागरिकता कानून में संशोधन दोनों अलग-अलग विषय हैं और उन्हें जोड़कर नहीं देखना चाहिए। नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्तावित विधेयक बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में प्रताड़ना के शिकार अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने से जुड़ा है और इस विधेयक के पास होने के बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली लोकसभा ने इस विधेयक को पास किया था और उसे प्रवर समिति ने भी हरी झंडी दे दी थी, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने के कारण विधेयक निरस्त हो गया। सरकार अब नए सिरे से इस विधेयक को संसद में लाएगी।

सरमा बोले, असम में दोबारा एनआरसी की जरूरत : असम के वित्त मंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिश्व सरमा ने राज्य में दोबारा एनआरसी की मांग की है। एक प्रेस कांफ्रेंस में उन्होंने कहा, 'असम सरकार ने एनआरसी को स्वीकार नहीं किया है। राज्य सरकार ने गृह मंत्रालय से मौजूदा एनआरसी को रद करने का अनुरोध किया है।' एनआरसी के राज्य संयोजक प्रतीक हजेला पर निशाना साधते हुए सरमा ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में राज्य सरकार को किनारे रखा गया था। सरमा ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने का समर्थन किया। साथ ही कहा कि सभी राज्यों में एनआरसी के लिए आधार वर्ष 1971 ही होना चाहिए। (पेज-3 भी देखें)

कुछ लोग एनआरसी लागू करने के नाम पर बंगाल में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं साफ करना चाहती हूं कि बंगाल में एनआरसी को अनुमति नहीं मिलेगी। कोई आपकी नागरिकता नहीं छीन सकता। - **ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री, बंगाल**

अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के बिल को मंजूरी

- कैबिनेट के फैसले से दिल्ली के 40 से 50 लाख लोग होंगे लाभान्वित
- इन कॉलोनियों में रहने वालों को उनके घरों पर मिलेगा मालिकाना हक

नई दिल्ली, प्रेट्र : दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोगों को केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के विधेयक को मंजूरी दे दी है। इसके जरिए वहां रहने वाले निवासियों को उनके घरों पर मालिकाना हक भी मिलेगा। राजनीतिक रूप से यह फैसला बहुत अहम है। माना जा रहा है कि इस फैसले से 40-50 लाख लोगों को लाभ होगा, जिनमें ज्यादातर गरीब तबके के हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

सूत्रों ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने वाले विधेयक को गुरुवार को संसद में पेश किया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि विधेयक को सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है। 23 अक्टूबर को कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजधानी की चिन्हित 1,797 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में इन कॉलोनियों से जुड़े संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात में विधेयक लाने की बात कही थी।

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने केंद्र सरकार पर इस मामले में विधेयक नहीं लाकर वादाखिलाफी का आरोप लगाया था।

दरअसल, मौजूदा नियमों के मुताबिक अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया दिल्ली सरकार की निगरानी और समन्वय से ही लागू होगी।

हालांकि, पिछले महीने जब कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, तब केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने कहा था कि इसका लाभ दिल्ली की 69 समृद्ध कॉलोनियों को नहीं मिलेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा चिन्हित की गई इन कॉलोनियों में सैनिक फॉर्म, महेंद्रू एंक्लेव और अनंतराम डेयरी भी शामिल है।

केंद्र सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले विधेयक के कानून बन जाने के बाद इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अपने घरों पर मालिकाना हक मिल जाएगा। वो घरों की खरीद-बिक्री कर सकेंगे। उनके घरों की रजिस्ट्री हो सकेगी। लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आस-पास की नियमित कॉलोनियों में मौजूदा सर्किल दर से उन्हें पेनाल्टी के साथ कुछ शुल्क चुकाने होंगे।

जासूसी मामले पर वाट्सएप ने जताया खेद

- सीईआरटी-इन ने वाट्सएप अकाउंट पर खतरे को लेकर जारी की एडवाइजरी
- कंपनी ने कहा, नए खतरे से किसी यूजर पर नहीं पड़ा प्रभाव

नई दिल्ली, प्रेट्र : इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफार्म वाट्सएप ने पेगासस जासूसी मामले पर खेद जताया है। कंपनी ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए वह सभी उपाय कर रही है। वहीं, देश की साइबर सुरक्षा एजेंसी ने चेतावनी जारी कर कहा है कि एक एमपी 4 फाइल भेजकर वाट्सएप को हैक किया जा सकता है। इस पर कंपनी ने कहा, नए खतरे से कोई यूजर प्रभावित नहीं हुआ है।

सरकारी सूत्रों ने नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि वाट्सएप ने सरकार को पत्र लिखकर जासूसी मामले पर खेद जताया है। सरकार ने वाट्सएप से अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने को कहा है। सरकार की तरफ से कंपनी को बता दिया गया है कि सुरक्षा को लेकर आगे अब किसी प्रकार की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंपनी ने कहा है कि साइबर सुरक्षा पर वह सरकार के साथ मिलकर काम करेगी।

इस बीच, वाट्सएप अकाउंट पर नए खतरे को लेकर जारी एडवाइजरी में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम-इंडिया (सीईआरटी-इन) ने कहा है कि एमपी 4 फाइल भेजकर वाट्सएप अकाउंट हैक करने का खतरा बढ़ रहा है। यह एडवाइजरी ऐसे समय में जारी की गई है, जबकि कुछ दिन पहले ही वाट्सएप ने सरकार को बताया था कि इजरायली एनएसओ ग्रुप के स्पाइवेयर पेगासस सॉफ्टवेयर द्वारा दुनियाभर में 1400 लोगों के वाट्सएप अकाउंट हैक किए गए थे। इनमें कुछ भारतीय पत्रकार व मानवाधिकार कार्यकर्ता भी थे।

लोगों की निजता की सुरक्षा के लिए सरकार प्रतिबद्ध

केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सरकार पेगासस स्पाइवेयर के जरिए मोबाइल यूजर के अकाउंट को हैक करने की कोशिश की खबर से अवगत है। उन्होंने एआइएमआइएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही। रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'नागरिकों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक तैयार करने पर काम कर रहा है तथा इसे संसद के पटल पर प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।' उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें गोपनीयता का अधिकार भी शामिल है।

हैकिंग से निपटने को आइटी एक्ट में हैं प्रावधान

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि हैंकिंग से निपटने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में पर्याप्त प्रावधान हैं। उन्होंने कहा कि सीईआरटी-इन ने इस साल 17 मई को एडवाइजरी जारी वाट्सएप यूजरों को अकाउंट हैक किए जाने के संभावित खतरे के प्रति आगाह किया था।

सरकार की छवि खराब करने की साजिश

रविशंकर प्रसाद ने लोगों के वाट्सएप अकाउंट पर निगरानी रखने के लिए पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदने की खबरों को भी भ्रामक बताया। उन्होंने कहा कि पेगासस जासूसी मामले की आड़ में इस तरह की खबरें सरकार की छवि खराब करने की साजिश के तहत फैलाई जा रही है।

महाराष्ट्र में सत्ता का सस्पेंस खात्मे की ओर

- कांग्रेस-राकांपा नेताओं की बैठक के बाद सहमति के आसार
- कांग्रेस नेता चव्हाण ने कहा, राज्य में जल्द एक स्थिर सरकार बनेगी
- राकांपा प्रवक्ता बोले, तीनों पार्टियों के साथ आए बिना नहीं बन सकती सरकार

नई दिल्ली में राकांपा प्रमुख शरद पवार के आवास पर बुधवार को राकांपा और कांग्रेस के नेताओं की बैठक हुई। प्रेट्र

नई दिल्ली, प्रेट्र : पिछले एक सप्ताह में हुई दर्जनों बैठकों के बावजूद महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बना असमंजस का दौर अब शायद खत्म हो गया है। दिल्ली में कांग्रेस-राकांपा के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद कांग्रेस नेता एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने साफ-साफ शब्दों में कहा, 'हम बहुत जल्द एक स्थिर सरकार बनाने जा रहे हैं।' वहीं राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने इशारों-इशारों में शिवसेना से गठबंधन की बात भी कह दी। उन्होंने कहा कि राज्य में तीनों पार्टियों के साथ आए बिना सरकार नहीं बन सकती। हाल के दिनों में कांग्रेस-राकांपा की तरफ से शिवसेना से गठबंधन को लेकर पहली बार इस तरह का स्पष्ट संकेत दिया गया है।

राकांपा प्रमुख शरद पवार के आवास पर दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं की बैठक के बाद चव्हाण ने कहा कि चर्चा सकारात्मक रही और जल्द ही नई सरकार का गठन हो जाएगा। हालांकि उन्होंने अभी एक-दो दिन और चर्चा चलने की बात कही है। वहीं, राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा, 'वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। चर्चा अभी चलेगी। तीनों पार्टियों के साथ आए बिना सरकार नहीं बन सकती।' बैठक में कांग्रेस के नेता अहमद पटेल, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे, पृथ्वीराज चव्हाण, केसी वेणुगोपाल और बालासाहेब थोराट ने हिस्सा लिया। राकांपा की ओर से सुप्रिया सुले, अजीत पवार, जयंत पाटिल व नवाब मलिक शामिल हुए।

ज्ञात हो, 24 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से सरकार गठन पर असमंजस की स्थिति है। चुनाव में भाजपा-शिवसेना गठबंधन को बहुमत मिला था, लेकिन ढाई साल के लिए मुख्यमंत्री पद पर शिवसेना के दावे के बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। 12 नवंबर को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया।

बन गया है फॉर्मूला : सूत्रों के अनुसार पवार के आवास पर हुई बैठक में महाराष्ट्र में सरकार गठन से जुड़ी रूपरेखा और साझा न्यूनतम कार्यक्रम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि कैबिनेट में 16 पद शिवसेना, 15 राकांपा और 12 कांग्रेस को मिल सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष का पद भी कांग्रेस को मिलने की उम्मीद है। पहले ढाई साल शिवसेना का और बाद के ढाई साल राकांपा का सीएम रहेगा। कांग्रेस को डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पवार ने की किसानों के मुद्दे पर चर्चा पेज>>4

दिखाई सक्रियता

संसदीय कमेटी ने पिछली बैठक से नदारद रहे अफसरों की खिंचाई की, अपने सदस्यों से सवाल तक नहीं किए, शहरी विकास मंत्रालय ने प्रदूषण से निपटने की योजना पेश की, पर्यावरण सचिव ने कहा, 15 फीसद कम हुआ प्रदूषण

प्रदूषण में सुधार के लिए अफसरों को अल्टीमेटम

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर संसदीय समिति ने बुधवार को जिम्मेदार अफसरों की जमकर खिंचाई की। साथ ही एक हफ्ते के भीतर प्रदूषण के बढ़े स्तर को कम करने का अल्टीमेटम भी दिया। कमेटी ने इस दौरान 15 नवंबर की बैठक में न पहुंचने वाले अफसरों की जमकर क्लास ली, उनसे लिखित में जवाब लिया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि उसी बैठक से नदारद रहे अपने सदस्यों से कमेटी ने किसी तरह के सवाल तक नहीं किए।

बहरहाल, ससंदीय समिति की यह बैठक काफी गहमागहमी भरी रही। इसमें कमेटी के कुल 29 सदस्यों में से 23 सदस्य मौजूद रहे। इनमें एमजे अकबर, हेमा मालिनी, गौतम गंभीर, दिग्विजय सिंह, संजय सिंह आदि शामिल थे। बैठक में पर्यावरण सचिव, शहरी विकास मंत्रालय के सचिव सहित डीडीए व सीपीसीबी के वरिष्ठ अधिकारी, सभी नगर निगमों के आयुक्त भी मौजूद थे। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बताया कि अफसरों ने एक हफ्ते के भीतर सुधार लाने का भरोसा दिलाया है। अगले हफ्ते फिर इस पर बात की जाएगी।

संसद भवन में बुधवार को भाजपा सांसद गौतम गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने को लेकर संसदीय समिति की एक बैठक में शामिल हुए। प्रेट्र

संसद भवन परिसर में करीब ढाई घंटे तक चली इस बैठक में पर्यावरण और शहरी विकास मंत्रालय ने संसदीय कमेटी के सामने प्रदूषण से निपटने का अपना प्लान भी रखा। ज्यादातर सांसद प्रदूषण की इस समस्या का एक तय समयसीमा के भीतर निराकरण चाहते थे। इस पर पर्यावरण सचिव ने बताया कि पिछले सालों में इससे निपटने को लेकर किए गए उपायों के चलते प्रदूषण में करीब 15 फीसद की कमी आई है। आने वाले दिनों में इसमें 20 फीसद और भी कमी देखने को मिलेगी।

पिछली बैठक में गायब रहे गंभीर ने पूछे सबसे ज्यादा सवाल : संसदीय समिति की बैठक में सबसे ज्यादा सवाल पूर्व क्रिकेटर और पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर के ही थे। हालांकि वह प्रदूषण को लेकर कमेटी की 15 नवंबर को बुलाई गई बैठक में अनुपस्थित रहे थे। जिसके चलते वह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए थे। साथ विपक्षी दलों ने भी उन पर सवाल उठाए थे। गंभीर ने गाजीपुर लैंडफिल साइट से कचरा उठाने में हो रही देरी पर सवाल किया। इस पर नगर निगम आयुक्त ने बताया कि वहां से हर दिन छह सौ गाड़ी कचरा उठाया जा रहा है, इस पर उन्होंने कहा कि वहां तो कचरा तो इससे ज्यादा पहुंच रहा है। इस पर आयुक्त ने जल्द ही इनमें तेजी लाने की बात कही।

पाल बोले, आला अफसर नहीं आएंगे तो बैठक नहीं होगी : संसदीय कमेटी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने बैठक शुरू होने से पहले ही साफ कर दिया कि यदि बैठक में सचिव स्तर के अधिकारी नहीं आएंगे, तो बैठक नहीं होगी। साथ ही वह इस मामले की शिकायत लोकसभा अध्यक्ष से भी करेंगे। जरूरत पड़ने पर इस मामले में कैबिनेट सचिव को बुलाया जाएगा।

भारत को 7100 करोड़ रुपये की नौसैनिक तोपें बेचेगा अमेरिका

नई दिल्ली, प्रेट्र : अमेरिका ने भारत को एक अरब डॉलर (करीब 7,100 करोड़ रुपये) की नौसैनिक तोपें बेचने का फैसला लिया है। बता दें कि बीते तीन साल में भारत ने करीब 5.67 अरब डॉलर के रक्षा समझौते किए हैं। लोकसभा में रक्षा राज्यमंत्री श्रीपद नाइक ने कहा कि दोनों देशों के बीच 21 रक्षा सौदे हुए हैं।

अमेरिका की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने मंगलवार को वाशिंगटन में जारी अधिसूचना में कहा, 13एमके-45 पांच इंच/62 कैलिबर (एमओडी-4) नौसैनिक तोपों और उनसे संबंधित उपकरणों की प्रस्तावित विदेशी सैन्य बिक्री की अनुमानित लागत 1.0210 अरब डॉलर है। इन तोपों का इस्तेमाल युद्धपोतों तथा युद्धक विमानों के खिलाफ और तटों पर बमबारी के लिए किया जाता है। इन तोपों का निर्माण बीएई सिस्टम्स लैंड एंड आर्मामेंट्स द्वारा किया जाएगा और प्रस्तावित बिक्री से भारत की क्षमता में इजाफा होगा और भारतीय नौसेना मौजूदा एवं भविष्य के खतरों से बेहतर ढंग से निपटने में सक्षम होगी।

जीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि न मिलने से पांच राज्य केंद्र सरकार से नाराज

इंद्रप्रीत सिंह, चंडीगढ़

- पंजाब, केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के वित्त मंत्रियों ने मांगी अगस्त व सितंबर की किश्तें

पंजाब, केरल, बंगाल, राजस्थान और दिल्ली ने अगस्त और सितंबर माह में मिलने वाली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) की क्षतिपूर्ति राशि जारी नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार से नाराजगी जताई है। बुधवार को दिल्ली में राज्यों के वित्त मंत्रियों पर आधारित इंपावर्ड कमेटी की बैठक के बाद पांचों राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस बारे में संयुक्त बयान जारी किया।

पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने बताया कि केंद्र सरकार इसका कोई वाजिब कारण नहीं बता रही है। इसके चलते राज्यों में वित्तीय संकट खड़ा हो गया है। कई राज्य ओवरड्राफ्ट में चले गए हैं। उन्होंने कहा, राज्यों की आमदनी का 60 फीसद हिस्सा जीएसटी से आता है। इतना बड़ा अंतर होने से राज्य सरकारें न तो बजट की प्लानिंग कर पा रही हैं और न ही रोजाना का खर्च चला पा रही हैं। उन्होंने कहा, जीएसटी लागू होने से पहले इंपावर्ड कमेटी की मीटिंग में आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि अगर केंद्र सरकार क्षतिपूर्ति की राशि नहीं देगी, तो राज्यों की वित्तीय स्थिति का क्या होगा? तब तय हुआ था कि यह राशि राज्यों को दी जाएगी। मौजूदा हालात ने उन राज्यों के विश्वास को हिला दिया है, जिन्होंने जीएसटी का समर्थन किया था।

गैर भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र पर बनाया दबाव : गैर भाजपा शासित राज्यों ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मांग की है कि वह लंबित राशि जारी करने के लिए मंत्रालय से कहें। वित्त मंत्रियों ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग बुलाने और एजेंडे में इस मुद्दे को शामिल करने की भी बात की, ताकि ऐसी स्थिति से निपटने का तरीका अपनाया जा सके।

क्या है क्षतिपूर्ति राशि : जीएसटी लागू होने से पहले राज्यों की वैट से जितनी आमदनी थी, यदि उतनी जीएसटी से नहीं आती तो राज्यों को केंद्र 14 फीसद की दर से क्षतिपूर्ति करती है।